07/2016

सप्रू हाउस पत्र

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने मध्य एशिया के साथ संबंधों को पुनःस्फूर्त बनाया

डॉ. अथर ज़फर

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्
सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने मध्य एशिया के साथ संबंधों को पुनः स्फूर्त बनाया

डॉ. अथर ज़फर

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने मध्य एशिया के साथ संबंधों को पुनः स्फूर्त बनाया

प्रथम प्रकाशन, 2016

प्रतिलिप्यधिकार © विश्व मामलों की भारतीय परिषद्.
आईएसबीएन : 978-93-83445-30-1

सभी अधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रकाशन का कोई भी भाग कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना , पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से , इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग , या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी विशेष रूप से लेखक के साथ है और उसकी व्याख्या , विश्व मामलों की भारतीय परिषद , नई दिल्ली के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्,
बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110 001, भारत
दूरभाष. : +91-11-23317242, फैक्स: +91-11-23322710
www.icwa.in

मुद्रण:
एल्फा ग्राफ़िक्स
6A/1, गंगा चैम्बर्स, डबल्यू.ई.ए., करोल बाग.
नई दिल्ली -110005 दूरभाष : 9312430311
ई-मेल : tarunberi2000@gmail.com

विषय-वस्तु

प्रस्तावना

मध्य एशिया का महत्त्व

भारत-मध्य एशिया संबंध

विकास संबंधी अनुपूरकता की तलाश

भारत-मध्य एशिया सुरक्षा सहयोग

भारत-मध्य एशिया संयोजनता

मध्य एशिया में क्षेत्रीय एकता

भारत-मध्य एशिया सांस्कृतिक सक्रिय सहयोग

सहयोग के लिए संभावना

तालिकाएं और आरेख **पृष्ठ सं.**

भारत और मध्य एशियाई राष्ट्रिकों की
प्रति व्यक्ति आय

मध्य-एशिया के साथ भारत का व्यापार, 2014-15

मध्य-एशिया के साथ भारत के व्यापार भाग का वितरण

प्रधान मंत्री मोदी की यात्रा ने मध्य एशिया के साथ संबंधों को पुनःस्फूर्त बनाया

परिचय

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में कजाकिस्तान के पांच मध्य एशियाई गणराज्यों , किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान का दौरा किया। किसी भी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी स्वतंत्रता के बाद से एक ही समय पर इन सभी पांच गणराज्यों की यह पहली यात्रा थी। यद्यपि जून 1955 में छह दशक पहले, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाँच गणराज्यों का दौरा किया था, लेकिन उस समय ये गणतंत्र सोवियत जनवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर) का हिस्सा थे।[1] भारत उन कुछ देशों में से था , जिन्हें इस क्षेत्र में पहुंच दी गई थी , जो सोवियत प्रणाली का हिस्सा था , और यह एकमात्र गैर-साम्यवादी देश था जिसने मध्य एशिया में एक राजनयिक मिशन स्थापित करने की अनुमति दी थी ।[2] पिछले 25 वर्षों में , अन्य नेताओं और अधिकारियों के अलावा प्रधानमत्रियों जैसे नरसिम्हा राव , अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह , और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य एशियाई गणराज्यों और प्रमुखों द्वारा लगातार यात्राओं का दौरा किया गया है तथा क्षेत्र के सरकार प्रमुखों और क्षेत्र के नेताओं ने नई दिल्ली की बार-बार यात्राएं की है।

इस पृष्ठभूमि में , प्रधान मंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण बन जाती है और विभिन्न क्षेत्रों के अनेक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए गए , जिनमें ऊर्जा, रक्षा और सैन्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, रेलवे, संस्कृति और खेल शामिल हैं। यात्रा के बीच में , प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के उफा के यूरेशियन शहर में आयोजित दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक शिखर बैठकों में भी भाग लिया - ब्राजील , रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) और

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)। एससीओ की बैठक में , मध्य एशियाई देशों के प्रधानमंत्रियों और नेताओं को फिर से एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण से मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इसका आयोजन क्षेत्र के गणराज्यों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की एक चौथाई सदी की पूर्व-संध्या पर किया गया था। दोनों पक्ष इस यात्रा का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे , जो उनके संबंधित पड़ोस में आर्थिक , सुरक्षा, ऊर्जा, संस्कृति सहित विद्यमान और नए क्षेत्रों के साथ-साथ आतंकवाद और उग्रवाद के आम खतरे से लड़ने के साथ-साथ नए क्षेत्रों की खोज करने, उन्हें गहन बनाने और उनके विस्तार में सहायक रहा है।

भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा ने दोनों पक्षों के समाजों विभिन्न वर्गों में फिर से उत्साह पैदा कर दिया है , जिसमें शिक्षाविद, राजनयिक, व्यापारी नेतृत्व और आम जनता शामिल है। क्षेत्र के प्रति नई दिल्ली की नीति ने न केवल द्विपक्षीय समझ को मजबूत किया है , बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को गति प्रदान करने के संकेत भी दिए हैं।

दोनों क्षेत्रों में एक-दूसरे के विकास को सहायता देने और उसमे तेज़ी लेन संसाधन क्षमता है , लेकिन आर्थिक मोर्चे और प्रत्यक्ष परिवहन संबंधों पर सीमित बातचीत से इसमें बाधा उत्पन्न होती है। मध्य एशियाई गणराज्यों के पास बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की माँगों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन हैं; दूसरी ओर, भारत एक अरब से अधिक का बाजार है और उसके वह साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न साथन भी प्रदान करता है , जैसे कम लागत वाली प्रौद्योगिकियां , कौशल और उद्यमिता विकास, सस्ता दूरसंचार, कुशल टेली-मेडिसिन, टेली-शिक्षा और फार्मास्यूटिकल्स जिससे इन गणराज्यों के विकास और विकास में तेजी लाई जा सकती है, जो इस क्षेत्र में बाहर और भीतर से हिंसा और उग्रवाद

के खतरे का सामना कर रहे हैं।

अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय बलों के हटने और अफगान राष्ट्रीय बलों द्वारा सुरक्षा की कमान संभालने के बाद देश में शांति और सुरक्षा अभी भी लचर बनी हुई है। तालिबान ने कई हमले किए हैं , जिनमें राजधानी काबुल पर हमले भी शामिल है। इसके नेता , मुल्ला उमर की मौत और तालिबान में नेतृत्व के मुद्दों की खबर ने राष्ट्रपति अशरफ गनी की गठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई शांति प्रक्रिया को और जटिल कर दिया है , जिन्होंने शांति को अपनी सरकार की 'सर्वोच्च प्राथमिकता' बनाया था।[3]अफगानिस्तान सरकार के साथ-साथ, भारत, मध्य एशियाई देश और क्षेत्रीय संगठन , जैसे एससीओ, जिसने अफगानिस्तान पर एक संपर्क समूह स्थापित किया है, जो परामर्श द्वारा अपनी गतिविधि संचालित करता है ,[4] द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से युद्ध से त्रस्त देश में शांति लाने और क्षेत्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले आतंकवाद से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए भारत को एससीओ की पूर्ण सदस्यता दी गई है। द्विपक्षीय स्तर पर , एससीओ के सदस्य देश पहले से ही अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाए हुए हैं , और पश्चातवर्ती परिदृश्य में , ये देश एससीओ मंच से अधिक भूमिका निभा सकते हैं, जहां अफगानिस्तान एक पर्यवेक्षक है। दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच विकास और आर्थिक तालमेल के लिए अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बहाल करने की आवश्यकता है जो भारत और मध्य एशिया का साझा पड़ोस है।

क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक और संभावित खतरा इराक और सीरिया इस्लामिक **राज्य** (आईएसआईएस) समूह का उदय और लोगों , खासकर क्षेत्र में युवाओं से अपील करने की उसकी क्षमता है। यह बताया गया है कि

मध्य एशियाई देशों के कई युवा आईएसआईएस समूह की ओर से लड़ने के लिए सीरिया और इराक गए हैं। आम युवाओं के अलावा, कुछ उच्च स्तर के अधिकारी **जो** प्रमुख पदों पर आसीन हैं और क्षेत्र की युवा **बालिकाओं** ने भी कथित तौर पर आईएसआईएस समूह के लिए अपने देशों को छोड़ दिया है। इस क्षेत्र से समूह के लिए प्रसिद्ध **'पक्षत्याग'** विशेषतः ताजिकिस्तान पुलिस प्रमुख, कर्नल गुलमुरोद खलीमोव का रहा है, जिन्हें अमेरिका और रूसी दोनों विशेष बलों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।[5] इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का अनुमान है कि मध्य एशियाई देशों के 2,000-4,000 लोग समूह में शामिल हो गए हैं। कट्टरपंथी /चरमपंथी ताकतों से जुड़ने की अपील वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों और नई पीढ़ी के एक वर्ग के आध्यात्मिक मानस से जुड़ी प्रतीत होती है। क्षेत्रीय नेता अपने देशों में सुरक्षा और सामाजिक स्थिति पर संभावित गिरावट के बारे में चिंतित हैं , जब ये लोग अपनी मातृभूमि पर लौटेंगे। इसके अलावा , यदि स्थानीय आतंकवादी समूह सीरिया और इराक में स्थित **आईएसआईएस** समूह के तत्वों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान (**आईएमयू**), ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (**ईटीआईएम**) और **जुंद अल-खलीफा** (**जेके**) क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन हैं और उनके अल कायदा और तालिबान से संबंध हैं। हाल ही में, **आईएमयू** के एक वरिष्ठ नेता, सईदुल्लाह उरगेनजी ने **आईएसआईएस** समूह के प्रति निष्ठा व्यक्त की है।[6]

इस विकसित सुरक्षा परिदृश्य में, प्रधानमंत्री मोदी की इस क्षेत्र की यात्रा को इस संदर्भ देखा जाना चाहिए कि भारत चुनौतियों का सामना करने में अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और वे मजबूत समर्थन के लिए भारत पर भरोसा कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में , वर्तमान पत्र मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के जुड़ाव और भविष्य में इसकी वृद्धि का विश्लेषण करता है। एक

क्षेत्र, जिसका महत्व , संसाधनों के संदर्भ में , भू-राजनीतिक स्थान और उभरते हुए बाजार हाल के दिनों में विकसित हुए हैं , इसके अलावा क्षेत्रीय देशों के सुरक्षा हितों में वृद्धि हुई है।

मध्य एशिया का महत्व

स्वतंत्रता के बाद से मध्य एशियाई देशों ने महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास किया है। ये गणराज्य विशाल हाइड्रोकार्बन संसाधनों, बड़ी मात्रा में खनिज भंडार, व्यापक जल-विद्युत क्षमता और कृषि-योग्य भूमि के विशाल हिस्सों से संपन्न हैं। इन पांच गणराज्यों के मध्य कजाखस्तान आकार में सबसे बड़ा देश है और 217 बिलियन यूएस डॉलर (डब्ल्यूबी , 2014) की सबसे बड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इसके पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का 12 प्रतिशत हिस्सा है और 2013 में इसने लगभग 22,550 टन का उत्पादन किया है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 38 प्रतिशत है।[7] कजाकिस्तान में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है और यह एक प्रमुख निर्यातक है।

उजबेकिस्तान दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और छठा सबसे बड़ा उत्पादक है ,[8] और यह क्षेत्र का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। उज्बेकिस्तान दोगुना स्थलरुद्ध देश है , जहां या देश और उसके निकटवर्ती पड़ोसी भी स्थलरुद्ध हैं; हालाँकि, यह क्षेत्र का ऐसा एकमात्र देश है जिसकी सभी मध्य एशियाई गणराज्यों और अफगानिस्तान के साथ सीमाएँ लगती हैं। यह उत्तरी वितरण नेटवर्क (एनडीएन) का 'केंद्र-बिंदु' था , जो सड़क, रेल और हवाई मार्गों का एक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क था जो यूरोप और अमेरिका से अफगानिस्तान में सेना को सामग्री की आपूर्ति करता था और कुल एनडीएन पारियात के लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा होता था। [9] देश में सोने

के महत्वपूर्ण भंडारों के साथ यूरेनियम जमा और हाइड्रोकार्बन भण्डार भी हैं। उजबेकिस्तान के पूर्वी पड़ोसी देश , ताजिकिस्तान में पर्याप्त जल-विद्युत क्षमता है, जो पूरे क्षेत्र की वर्तमान ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। देश का सामान्य संभावित भंडार प्रति वर्ष 527 बिलियन केडब्ल्यूएच है, जो पूरे मध्य एशिया की वर्तमान बिजली खपत से तीन गुना अधिक है। [10] इसके अलावा , देश में गोर्नो-बड़ाखशान क्षेत्र में तेल भण्डार और बहुमूल्य रत्न भी विद्यमान हैं।

ताजिकिस्तान का उत्तरी पड़ोसी देश , किर्गिस्तान, जल-विद्युत क्षमता के साथ-साथ सोने के भंडार में भी समृद्ध है। देश की तियान शान पर्वतमाला में स्थित सोने की खदानें इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से हैं और 2014 में किर्गिस्तान के कुल निर्यात में सोने का निर्यात लगभग 40 प्रतिशत था।[11]देश में पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि 5.5 मिलियन लोगों का एक छोटा देश होने के बावजूद , किर्गिस्तान ने 2013 में 3 मिलियन पर्यटकों आए। किर्गिस्तान भी परिवर्तन अपनाने के लिए उत्सुक रहता है और यह राष्ट्रीय मुद्रा शुरू करने, भूमि के निजीकरण की शुरुआत करने वाला मध्य एशिया का पहला देश बन गया तथा यह विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और इसने लोकतंत्र के संसदीय रूप के साथ प्रयोग भी किया।

तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जो 'स्थायी तटस्थता ' की नीति का पालन करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुसमर्थन भी दिया गया है, और इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार [12] है। इसे मध्य एशिया में स्थिरता का द्वीप'कहा जाता है।[13]

खनिज संपदा और ऊर्जा संसाधनों के अलावा , मध्य एशिया भी बढ़ते

मध्यम वर्ग और अपेक्षाकृत युवा आबादी के साथ एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभर रहा है। भारत , चीन, रूस, तुर्की और ईरान सहित क्षेत्रीय देश , विशेष रूप से परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कई पश्चिमी बहु-राष्ट्रीय निगमों (बहुराष्ट्रीय कंपनियों) के साथ क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

इस क्षेत्र में आने वाला निवेश, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो विकासशील क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मांग में हैं और विदेशों से भेजे गए धन-प्रेषण , विशेष रूप से ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के लिए, मध्य एशिया के 65 मिलियन लोगों के लिए आर्थिक लाभांश प्रदान कर रहे हैं। तथापि , धन-प्रेषण के बावजूद ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान अब तक अपनी आबादी की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधन क्षमता का प्रभावी ढंग से दोहन करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिरता और विकसित होती अर्थव्यवस्थाएँ इस क्षेत्र को निवेश , व्यापार, संचार और व्यापार के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती हैं।

अपने देशों में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए , मध्य एशियाई नेता अंतर्राष्ट्रीय निवेशों की ओर देख रहे हैं , जो व्यापार के नियम स्पष्ट होने पर दीर्घकालिक संभावनाएं प्रदान कर सकते हैं।

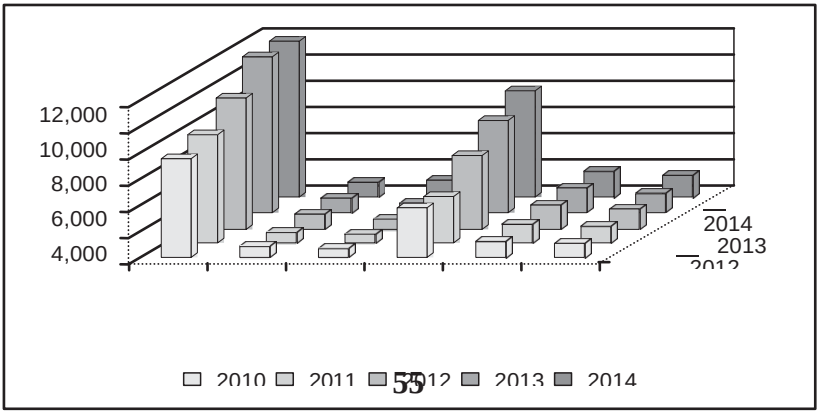

भारतीय और मध्य एशियाई राष्ट्रिकों की प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान यूएस डॉलर, स्रोत : विश्व बैंक[14]

मध्य एशियाई देश अपने नियमों और विनियमों में उपयुक्त बदलाव लाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दीर्घकालिक व्यापार और विदेशी सहयोगियों के साथ व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाया जा सके। किर्गिज़ गणराज्य 1998 में डब्ल्यूटीओ में शामिल होने वाला क्षेत्र से पहला देश था , इसके बाद 2013 में ताजिकिस्तान शामिल हुआ; और लंबी वार्ता के बाद, कजाखस्तान जुलाई 2015 में संगठन में शामिल हो गया। अन्य दो गणराज्य , तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इस विश्व व्यापार निकाय में शामिल होने के लिए डब्ल्यूटीओ के साथ बातचीत कर रहे हैं।

क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और भौगोलिक क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए, क्षेत्र की बड़ी आर्थिक शक्तियों ने अलग-अलग पहल की हैं। रूस ने जनवरी 2015 से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईईयू) का उद्घाटन किया है, जिसमें कजाकिस्तान और किर्गिस्तान मध्य एशिया से सदस्य हैं , जबकि आर्मेनिया और बेलारूस नई पहल के अन्य सदस्य हैं। इसी प्रकार , चीन ने मध्य एशिया में निवेश करने और उस क्षेत्र के माध्यम से इसके

पश्चिम में स्थित बाजारों तक पहुँच बनाने हेतु अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) अथवा रोड एंड बेल्ट पहल के भाग के रूप में इस क्षेत्र के लिए सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की प्रमुख अवसंरचना निवेश और आर्थिक एकीकरण योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि मध्य एशियाई देश स्वयं स्थलरुद्ध हैं, यह क्षेत्र एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में उभरा है और एशिया और यूरोप के बीच एक कड़ी बन गया है। दिसंबर 2014 में , यिवु, चीन से एक रेलगाड़ी, 13,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी का सफ़र तय करते हुए मैड्रिड, स्पेन तक पहुंचा करती थी। [15] परिवहन समय को छह से दो सप्ताह तक कम करने के अलावा, मार्ग में कार्बन फुटप्रिंट भी निम्न है। एक नियमित रेल सेवा पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है, जो दक्षिण-पश्चिमी चीनी शहर चोंगक्विंग को जर्मनी में दुसीबर्ग से जोड़ती है और पाँच सप्ताह के परिवहन समय को लगभग दो सप्ताह तक कम करती है , और इसमें हवाई परिवहन की तुलना में 80 प्रतिशत कम लागत आती है। [16] कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होकर गुजरते हुए, फरवरी 2016 में चीन से पहली 'सिल्क रोड' कार्गो ट्रेन तेहरान पहुँची। इसने ईरान और चीन के बीच समुद्र के माध्यम से लगने वाले परिवहन के 30 दिन समय को घटाकर लगभग दो सप्ताह कर दिया।

अपनी आर्थिक क्षमताओं और भौगोलिक लाभ का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए , क्षेत्रीय देश अवसरंचना का विकास कर रहे हैं , अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार कर रहे हैं और वैश्विक व्यापार व्यवस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं तथा क्षेत्रीय पहलकदम संचालित रहे हैं। 2014 में चीन और यूरोप के बीच व्यापार पारियात लगभग 615 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और कजाकिस्तान एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरकर तथा प्रमुख कार्गो संचालक दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड से सहायता लेकर सामुद्रिक लदान से इस

यातायात का 10 वाँ हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। 17 देश ने इस उद्देश्य के लिए चीन के साथ लगी खोरगोस सीमा के पास एक शुष्क पत्तन विकसित किया है, जो सबसे बड़े शहर और वाणिज्यिक हब अलमाटी से 300 किमी की दूरी पर है।

विशेष रूप से ऐसे गणतंत्र , जो आर्थिक रूप से हाइड्रोकार्बन पर निर्भर हैं , जैसे कि कजाखस्तान , अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता ला रहे हैं और आर्थिक और व्यापार भागीदारों की तलाश कर रहे हैं। भारत ने , जो हाल के वर्षों में एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है , अपनी 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था, व्यापक होते मध्यम वर्ग तथा विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के लिए बढ़ती आवश्यकता के फलस्वरूप मध्य एशियाई देशों के साथ अधिक भूमिका निभाने और अपने अनुभवों को साझा करने तथा अपने विकास के मार्ग में मध्य एशियाई देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने की इच्छा दिखाई है।

भारत-मध्य एशिया संबंध

भारत और मध्य एशिया के क्षेत्र में गहन ऐतिहासिक , सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं ; प्रसिद्ध 'रेशम मार्ग' और 'मसाला मार्ग' ने न केवल व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया , बल्कि सदियों से लोगों के लोगों के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र और उससे आगे मुक्त विचारों और सोच को प्रसारित होने को सुकर बनाया। अतीत में , बौद्ध धर्म, जो भारत में उत्पन्न हुआ और विकसित हुआ, का मध्य एशिया में लोगों द्वारा स्वागत किया गया और इसी प्रकार , भारत में विद्यमान अनेक लोकप्रिय सूफी घरानों की जड़ें उस क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र से उद्भूत होने वाले शक और कुषाण , मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के दो क्षेत्रों को साझे राजनीतिक नियंत्रण में ले आए थे। मध्ययुगीन काल के दौरान भाषाई हस्तक्षेप ने एक नया और अनोखा विद्यालय स्थापित किया , जिसे सबक-ए-हिंदी या फारसी साहित्य में भारतीय विद्यालय कहा जाता था। इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता की अवधि के दौरान भी , भारत और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क जारी रहा। फिर भी , अगर सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंधों ने अतीत में दोनों पक्षों को बांधे रखा है ; तो समकालीन समय में , अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वाणिज्य के लिए संयोजनीयता ऐसे प्रमुख कारक हैं जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाते हैं।

भारत और मध्य एशिया के क्षेत्र के बीच संबंध मजबूत और गहन हो रहा है क्योंकि ये गणराज्य 1991 में स्वतंत्र देश बन गए और दुनिया को जोड़ने के लिए बहु-आयामी नीति को अपनाया। दोनों पक्षों के बीच न केवल राजनीतिक स्तरों पर लगातार दौरे आयोजित किए गए हैं , बल्कि पिछले अनेक वर्षों से लोगों के लोगों के साथ संपर्क भी मजबूत हुए हैं। भारत के

कई छात्र अपने चिकित्सा पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए मध्य एशियाई गणराज्यों में जाते हैं और क्षेत्र के छात्र भारतीय संस्थानों में पढ़ने आते हैं। पाँच गणराज्यों में से तीन अब भारत के रणनीतिक साझेदार हैं। मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों के दो दशक पूरा होने के अवसर पर और क्षेत्र के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए , नई दिल्ली द्वारा 2012 में बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित ट्रैक II स्तरीय प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता के दौरान 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति की घोषणा की गई। वार्षिक वार्ता पांच गणराज्यों और भारत के शिक्षाविदों , चिकित्सकों, अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं को किसी एक गणतंत्र में एक साथ लेकर आती है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच सहयोग की संभावना पर चर्चा की जाती है। भारत में नई सरकार ने देश की विदेश नीति पर नया बल प्रदान किया है ताकि पड़ोसी क्षेत्र को भी विस्तारित आर्थिक वृद्धि में शामिल किया जा सके। इस तथ्य को इस बात से भी देखा जा सकता है कि अपने उद्घाटन के दौरान , प्रधानमंत्री ने पहली बार पड़ोसी देशों की सरकारों के नेताओं को आमंत्रित किया था। वैश्विक और आर्थिक रूप से परस्पर जुड़े विश्व में , प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए देश की विदेश नीति का गहनता से अनुसरण करते हैं। हाइड्रोकार्बन और यूरेनियम सहित देश की ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों के लिए निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने के लिए , उनकी मध्य एशियाई यात्रा राजनयिकता को गहन बनाने , व्यापार बढ़ाने और क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने पर केंद्रित थी। सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंधों के बावजूद, व्यापार अपनी क्षमता से बहुत नीचे रहा है ; 2014 में, यह केवल 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नवीकृत तरीके से प्रयास किए जाने के साथ-साथ राजनयिकता सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी।

मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार, 2014-15 (मिलियन यूएस डॉलर)

	कजाखस्तान	किर्गिस्तान	ताजिकिस्तान	तुर्कमेनिस्तान	उज्बेकिस्तान
निर्यात	250.68	37.76	53.71	91.98	170.44
आयत	701.67	0.77	4.39	13.05	55.86
विकास %	3.76	9.52	5.38	19.72	55.47
कुल व्यापार	952.35	38.53	58.09	105.03	226.31

स्रोत : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

व्यापार की अड़चनें

सीधी सड़क और रेल संपर्क न होने के कारण भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध प्रभावित हुए हैं , जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है और समय भी अधिक लगा है जिससे माल कम प्रतिस्पर्धी बना है। भारत से भेजे गए कंटेनर, क्षेत्र में अन्य देशों के माध्यम से पारेषित किए जाते हैं, जिसे कारण वे या तो पारगमन देश में भीड़-भाड़ होने के कारण या पारगमन देश से उत्पन्न होने वाले माल के निर्यात को दी गई वरीयता के कारण विलंबित हो जाते हैं। क्षेत्र के कुछ देशों में सीमित वीज़ा व्यवस्था और सीमित हवाई संपर्क भी इस क्षेत्र की व्यावसायिक यात्राओं को प्रभावित करते हैं। वीजा की कम संख्या का अर्थ हवाई यात्रियों की कम संख्या है , जो वाणिज्यिक उड़ानों को अव्यवहार्य बनाता है। यद्यपि यह क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध है , फिर भी बंदरगाहों तक सीधे रेल संपर्क न होने के कारण, उनका निष्कर्षण और निर्यात गैर-व्यवहार्य हो जाता है। हालांकि , परमाणु समझौते के बाद कजाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान रेलवे लाइन के उद्घाटन और ईरान पर प्रतिबंधों को हटाए जाने से क्षेत्रीय

रेल और ईरान में समुद्री लिंक के माध्यम से मध्य एशिया से भारत तक बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों और मॉल के किफायती और तेज संचलन की संभावनाएं खोल दी हैं।

मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार भाग का वितरण

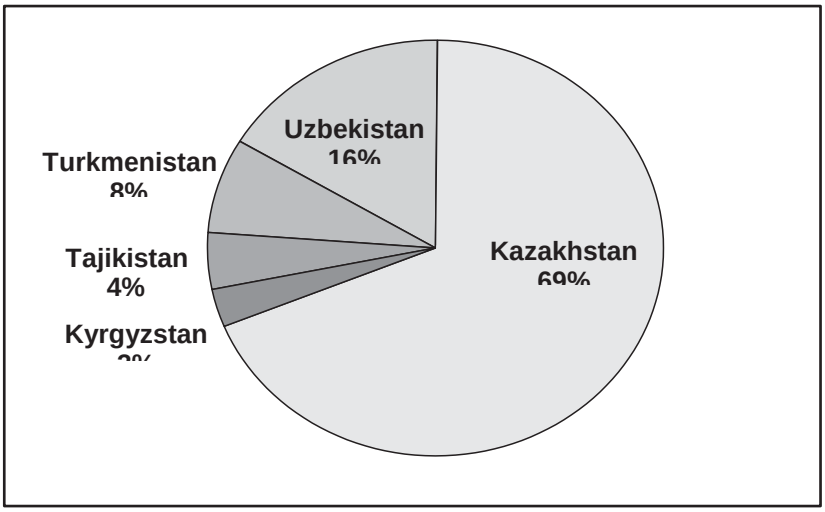

स्रोत : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

मध्य एशियाई देशों में भारतीय बैंकों की व्यापक उपस्थिति क्षेत्र के साथ देश के व्यापार को बढ़ावा देगी। मध्य एशियाई देशों में व्यवसाय करने वाले भारतीय व्यापारियों ने लेखक के साथ बातचीत में कहा कि इन गणराज्यों में भारतीय बैंकों की गैर-मौजूदगी से वित्तीय लेनदेन में होने वाली देरी के कारण द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। कजाकिस्तान में भारत के पंजाब नेशनल बैंक की एक अनुषंगी मौजूद है। क्षेत्रीय राजधानियों में भारतीय बैंक की शाखाएं लेनदेन को सुचारू करेंगी। वैकल्पिक रूप से , पारस्परिक समझौते और ई-कनेक्टिविटी का उपयोग करके , बैंक शाखा में विद्यमान टर्मिनल संबंधित देश में भारतीय बैंक आउटलेट के रूप में काम

कर सकता **है।**

विकास के पूरकों की तलाश

भारत और मध्य एशियाई देश कई आर्थिक पूरक साझा करते हैं और आपसी प्रगति के लिए मजबूत साझेदारी कायम कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बनाए रखने ; बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने ; और रोजगार सृजन के साथ सतत विकास को प्राप्त करने के लिए देश को ऊर्जा और खनिज संसाधनों की निर्बाध और आर्थिक रूप से व्यवहार्य आपूर्ति की आवश्यकता है , जिसमें हाइड्रोकार्बन और आण्विक सामग्री , भूमि के विशाल क्षेत्र और संधारणीय स्तर पर कृषि उत्पादन शामिल हैं। देश द्वारा आवश्यक संसाधन पास के मध्य एशिया में उपलब्ध हैं और क्षेत्र के गणतंत्र साझे आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सक्रिय भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा , भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी और आईटीईएस क्षेत्रों , भेषजिक, अनुसंधान और विकास , सेवा क्षेत्र तथा कृषि और पशुपालन में विशेषज्ञता विकसित की है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विकास करना मध्य एशियाई देशों का लक्ष्य है। नई दिल्ली मध्य एशियाई देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है , जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने और अपने लोगों के लिए सामाजिक विकास लाने के लिए उत्सुक हैं। ये गणराज्य ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध हैं और अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए संभावित बाजारों की तलाश कर रहे हैं। रूस और चीन अपने ऊर्जा निर्यात की दो प्रमुख दिशाएँ हैं ; ये गणराज्य गंतव्यों को विविधता प्रदान करना चाहते हैं और इसमें दक्षिण एशिया भी शामिल है , जिसमें ऊर्जा की कमी है और एक संभावित बड़ा बाजार है। भारत को , अपनी प्रभावशाली विकास दर के साथ , मध्य एशियाई देशों द्वारा सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए एक संभावित भागीदार और निवेशक के रूप में

देखा जाता है।

ऊर्जा की कमी वाला भारत अपनी ऊर्जा क्षमता में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें यूरेनियम की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। कज़ाकिस्तान दुनिया में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, भारत और कजाकिस्तान के बीच प्राकृतिक यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। [18] इस सौदे के अनुसार , कजाकिस्तान 2019 [19] तक भारत को 5 ,000 टन प्राकृतिक यूरेनियम वितरित करेगा , जिससे यह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद देश के लिए यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगा। वर्ष 2009 के बाद से यह अस्ताना और दिल्ली के बीच दूसरा ऐसा समझौता है। पिछले ऐसे समझौते के अनुसार , जो 2014 में समाप्त हो गया था , कजाकिस्तान ने 2010-11 में 600 मीट्रिक टन , 2011-12 में 350 मीट्रिक टन , 2012-13 में 402.5 मीट्रिक टन और 2013-14.20 में 460 मीट्रिक टन यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति की।[20]

कजाकिस्तान के भी कैस्पियन क्षेत्र में महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन भंडार हैं , जो दुनिया के तेल और गैस के कुल भंडार का लगभग चार से पांच प्रतिशत है, और यह तेल भंडार में शीर्ष 15 देशों में से है। [21] भारत ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने 2011 में बेसिन में सत्पयेव अपतटीय खंड में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी अर्जित की।[22] यह खंड लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग के उथले पानी में स्थित है। अन्वेषणकारी ड्रिलिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2015 में इस देश की यात्रा के दौरान किया गया था।

संसाधन राजनयिकता पर दिए गए नवीकृत बल के अंतर्गत आने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजना मध्य एशिया से दक्षिण एशिया के लिए तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। यह परियोजना लंबे समय से प्रस्तावित है ; हालाँकि, अपने मध्य एशिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के फलस्वरूप तुर्कमेनिस्तान से अनुमानतः 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन भारत को दी गई है जिससे भारत को अपेक्षित बल मिलेगा। संयुक्त वक्तव्य में पाइपलाइन परियोजना को 'दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।[23]

पाइपलाइन अनेक वर्षों से विलंब का सामना कर रही है और इसमें मुख्य मुद्दा परियोजना के लिए एक कंसोर्टियम नेता का चयन था। रुचि रखने वाले तेल के क्षेत्र विदेशी दिग्गज, जैसे शेवरॉन और एक्सॉन, कंसोर्टियम का नेतृत्व करने के लिए तुर्कमेनिस्तान के गैस क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहते थे , जिसके लिए तुर्कमेन सरकार सहमत नहीं थी।[24] इस मुद्दे को अब हल कर लिया गया है और एक कंसोर्टियम के नेता के चयन को परियोजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जाता है जिसकी 2018 में परिचालन की परिकल्पना की गई है। परियोजना पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ध्यान से संकेत ग्रहण करते हुए और विश्व शक्तियों के साथ ईरानी परमाणु समझौते के बाद , जब ईरान से ऊर्जा स्रोतों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शामिल होने की आशा है और रूस इसकी गैस की कम खरीद कर रहा है, [25] तुर्कमेनिस्तान ने परियोजना को लागू करने और कंसोर्टियम का नेतृत्व करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। इस देश में दुनिया का चौथा सबसे व्यापक सिद्ध गैस भंडार है [26] और यह अपने निर्यात में विविधता लाने और दक्षिण एशिया में गैस बाजारों को हासिल

करने का अवसर नहीं खोना चाहता है। टीएपीए के सभी साझेदार तुर्कमेनिस्तान सरकार की कंपनी तुर्कमेन गाज को कंसोर्टियम लीडर[27] बनने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गए हैं , जो मध्य एशिया के ऊर्जा भंडारों को दक्षिण एशिया में ऊर्जा बाजारों से जोड़ने वाली पाइपलाइन का निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन करेगी।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ जिन्होंने मई 2015 में तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था, ने भी टीएपीआई के 'कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए' राष्ट्रपति गुरबंगुली बेर्दिमुहामेदोव पर 'दबाव बनाया'।[28] इसके अलावा , क्षेत्र की यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी भी उफा, रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ बैठकें कीं। ये घटनाक्रम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्षेत्रीय देश दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं और ईरानी परमाणु समझौता संबंधों में तेजी ला सकता है।

अक्टूबर 2014 में, अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस इंजीनियरिंग समूह , पेनस्पेन को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा तुर्कमेनिस्तान के व्यापक गैलकाइनिश गैस क्षेत्र से अफ़गानिस्तान , पाकिस्तान और भारत के ऊर्जा बाजारों के लिए 1,820 किलोमीटर लंबी और 56 इंच व्यास की पाइपलाइन के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था।[29] आपूर्ति की जाने वाली गैस के प्रमुख हिस्से से भारत और पाकिस्तान में ऊर्जा आवश्यकताओं में होने वाली वृद्धि को पूरा करने में मदद मिलेगी , जिसके 2030 तक दोगुना होने की आशा है।[30] व्यवहार्यता अध्ययन के पूरा होने के बाद , तुर्कमेनिस्तान ने दिसंबर 2015 से पाइपलाइन निर्माण शुरू कर दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी , तुर्कमेनिस्तान के

राष्ट्रपति गुरबंगुली बेर्दिमुहामेदोव, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिसंबर 2015 में पाइपलाइन के 'शिलान्यास' समारोह में भाग लिया।[31]

फिर भी, मध्य एशिया के दक्षिण एशिया के साथ अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक संबंध, उसके लिए ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति तथा व्यापार और वाणिज्य तभी प्रारंभ हो सकता है और समृद्ध बन सकता है जब उनका साझा पड़ोस, यानी, अफगानिस्तान एक स्थिर और सक्षम संयोजक बन जाता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय बल देश से वापस जा रहे हैं और सुरक्षा की कमान अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के पास है, फिर भी, देश में सुरक्षा स्थिति में सुधार होना अभी बाकी है; और काबुल में भी लगातार हमले होते रहते हैं।

तालिबान के साथ बातचीत या सुलह प्रक्रिया, जिसे अशरफ़ घानी सरकार ने अपनी प्राथमिकता बताया है, ने अब तक निर्णायक नतीजे नहीं निकले हैं। मुल्ला उमर की मौत की रिपोर्ट और तालिबान के नए नेतृत्व द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग ने अनिश्चितता के माहौल में और भी वृद्धि कर दी है।

अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति और गृह-युद्ध ने काबुल के साथ नई दिल्ली और आगे मध्य एशियाई देशों संबंधों में बाधा उत्पन्न की है। भारत 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की अपनी प्रतिबद्धता के साथ अफगानिस्तान में स्थायित्व लाने के प्रयास कर रहा है जो क्षेत्रीय देशों में सबसे अधिक है। भारतीय सहायता क्षमता निर्माण , कौशल वृद्धि , अवसरंचना के विकास , कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और स्वास्थ्य सेवा आदि पर केंद्रित है। भारत को आम अफगान लोगों के बीच एक सकारात्मक सहायक देश के रूप में भी देखा जाता है। अफगानिस्तान में भारत के क्रियाकलापों के कुछ उदाहरण हैं - जारंज-डेलाराम सड़क , सलमा

बांध विद्युत् परियोजना , पुल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन , काबुल, जलालाबाद, कंधार, हेरात और मजार-ए-शरीफ में स्कूल और अस्पताल तथा कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएसटीयू)। भारत ने अफगानिस्तान में व्यापक निवेश किया है और वह चाहता है कि देश में स्थायित्व कायम हो, और यही मध्य एशियाई देशों के साथ-साथ ईरान, अफगानिस्तान के पश्चिमी पड़ोसी की इच्छा भी है। भारत, मध्य एशिया और क्षेत्रीय देशों के पास अफगानिस्तान को स्थिर बनाने में मदद करने हेतु अपने अंतर-क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए साझा एजेंडा है।

भारत-मध्य एशिया सुरक्षा सहयोग

पांच मध्य एशियाई गणराज्यों में से तीन देश अर्थात ताजिकिस्तान , उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमाएं तथा साथ ही नृजातीयताएं भी साझा करते हैं और यह देश मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक कड़ी है। सभी प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति परियोजनाएं , जिनमें टीएपीए और सीएएसए -1000[1] बिजली पारेषण लाइन भी शामिल हैं, अफगानिस्तान से होकर गुजरती हैं। अस्थिरता और अस्त-व्यस्तता ऊर्जा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और मध्य एशियाई गणराज्यों को अफगानिस्तान के माध्यम से दक्षिण एशियाई आर्थिक प्रणाली से जोड़ने के मार्ग में बाधाएं हैं। इसके अलावा , अफगानिस्तान-पाकिस्तान में व्याप्त असुरक्षा दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में सुरक्षा को प्रभावित करती है। अनेक उग्रवादियों और आतंकवादियों ने इन दोनों देशों में शरण ली है और मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंसक हमले किए हैं। मध्य एशिया के इस्लामी आतंकवादी समूह , जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ उज़्बेकिस्तान (आईएमयू), इस क्षेत्र में सरकारों को उखाड़ फेंकना और खिलाफत का माहौल स्थापित करना चाहते हैं। विश्लेषकों को डर है कि एक उत्साह से भरा और राजनीतिक रूप से वैध तालिबान उनमें से अनेक को

अपने देशों में लौटने के लिए प्रोत्साहित करेगा , जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और असुरक्षा पैदा होगी। दूसरी ओर, तालिबान ने मध्य एशिया की सीमा के साथ लगे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है; यह सीमा 2,387 किलोमीटर लंबी है,[32] और केवल उज्बेकिस्तान ही अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा की प्रभावी रूप से निगरानी करने में सक्षम है।[33]

---

1 मध्य एशिया दक्षिण एशिया अथवा सीएएसए -1000 ट्रांसमिशन लाइन परियोजना किर्गिज़ गणराज्य और ताजिकिस्तान (पहले 477 किलोमीटर) और ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान (अगले 750 किलोमीटर) के बीच उच्च वोल्टेज पर विद्युत् संप्रेषित करेगी। http: www.casa-1000.org.

इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ग्रुप का उदय अफगानिस्तान और पड़ोसी मध्य एशिया में सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक और खतरा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह के अनुमानों के अनुसार , मध्य एशिया से 2,000 से 4 ,000 व्यक्ति सीरिया में ग्रुप में शामिल हो गए हैं। [34] ताजिक लोग ताजिकिस्तान की विशेष पुलिस के प्रमुख कर्नल गुलमुरोद खलीमोव द्वारा किए गए इस्लामिक स्टेट में 'दलबदल' के सदमे से अभी उबरे ही थे कि देश ने पूर्व उप रक्षा मंत्री अब्दुखलीम नज़रज़ोदा द्वारा किए गए 'विद्रोह' के रूप में देश के सम्मुख एक और सुरक्षा चुनौती पेश की। [35] सितंबर 2015 में, राजधानी दुशांबे के निकट पुलिस से झड़प में 20 से अधिक लोग मारे गए। ताजिकिस्तान सरकार ने उप रक्षा मंत्री नज़रज़ोदा को बर्खास्त कर दिया तथा उन पर उग्रवादी समूह बनाने और पुलिस के साथ संघर्ष में उग्रवादियों की मदद करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने अपने ग्रुप पर इस्लामिक स्टेट के साथ वैचारिक संबंध रखने का आरोप लगाया।[36] सरकार के बलों द्वारा शुरू किए गए एक ऑपरेशन के दौरान 16 सितंबर को पूर्व उप रक्षा मंत्री को उनके सहयोगियों के साथ मार दिया गया था।[37] अब्दुखलीम नज़रज़ोदा पांच-वर्षीय गृहयुद्ध (1992-97) के दौरान यूनाइटेड ताजिक विरोधी दल के एक सेनानी थे, जो 1997 में एक समझौते के साथ समाप्त हुआ जिसने विद्रोहियों को सरकार में शामिल होने की अनुमति दी।

सरकार और विपक्षी इस्लामवादियों के बीच तनाव हाल के महीनों में बढ़ रहा है। सरकार ने ताजिकिस्तान (आईआरपीटी) के इस्लामिक पुनर्जागरण पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है और अपने सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे समाज में और अधिक चिंता पैदा हो गई है कि पार्टी भूमिगत हो सकती है या संगठन को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर नेतृत्व उभर सकता है। आईआरपीटी के नेता, मुहिद्दीन कबीरी तुर्की में हैं और उन्होंने

चेतावनी दी है कि उनकी पार्टी पर सरकार द्वारा डाले गए दबाव से इस्लामवादी चरमपंथ बढ़ सकता है।[38]

कई युवा मध्य एशियाई लोग अकुशल कार्यों को करने के लिए रूस जाते हैं और वे अपने देश में स्थित परिवारों को घर चलाने के लिए धन-प्रेषण करते हैं। एक मिलियन से अधिक किर्गिज़ लोग और एक मिलियन से अधिक ताजिक, जो प्रत्येक देश के कर्मचारियों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, रूस में काम कर रहे हैं।[39] यूक्रेनी मुद्दों पर रूस के प्रतिबंधों ने इन देशों के श्रमिकों को भी प्रभावित किया है , जिससे हजारों लोग बिना नौकरी के और धनहीन हो गए हैं , और इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट की भर्तियों के आसान लक्ष्य बनते जा रहे हैं। [40] बेरोजगारी, गरीबी, धार्मिक प्रेरणा, उनके अपने घरेलू देशों में धार्मिक प्रथाओं पर अंकुश कुछ ऐसे कारण हैं, जो इस क्षेत्र के युवाओं को, उन अन्य क्षेत्रों के विपरीत आईएसआईएस आतंकी समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ,[41] जहां विचारधारा प्रेरक शक्ति हो सकती है। सितंबर 2015 में, उज्बेकिस्तान सरकार ने देश भर की मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज या ईद में भाग लेने से 18 साल से कम उम्र के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश में कहा गया है कि बच्चों के माता-पिता, अगर प्रार्थना के दौरान एक मस्जिद के अंदर पाए जाते हैं , तो उन पर 750 यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा , जो न्यूनतम मजदूरी के अनुसार 15 महीने के वेतन के बराबर है।

आईएसआईएस समूह दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है और एक अस्थिर अफगानिस्तान इसके लिए एक उपयुक्त भर्ती मैदान बन सकता है। मुल्ला उमर की मौत की खबर के बाद, तालिबान के नेतृत्व द्वारा संकट का सामना किए जाने के बारे में रिपोर्ट के मुताबिक , तालिबान के कुछ कमांडरों ने इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा जताई है और हत्याओं

को अंजाम दिया है , जिसकी तालिबान द्वारा की निंदा की है , और उन्हें 'गैर-जिम्मेदार अज्ञानी व्यक्ति' करार दिया है। [43] सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अफ़गानिस्तान और इस क्षेत्र में, प्रधानमंत्री द्वारा इस क्षेत्र का दौरा एक मित्र देश से लेकर मध्य एशियाई गणराज्यों तक एक प्रकार की एकजुटता का प्रदर्शन था कि भारत दोनों क्षेत्रों के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए उनके साथ खड़ा है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, इस्लाम करीमोव के साथ बैठक के बाद , प्रधानमंत्री ने कहा: "हमने अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हमने अपने विस्तारित पड़ोस में उग्रवाद और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भी चिंताओं को साझा किया है।"[44]

प्रधानमंत्री की मध्य एशिया के देशों की यात्रा के दौरान सुरक्षा , आतंकवाद-रोधी उपाय और रक्षा सहयोग चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दा थे , क्योंकि ये मुद्दे मेजबान देशों के साथ जारी किए गए संयुक्त वक्तव्यों के साझे विषय हैं। भारत अपने रक्षा और सुरक्षा संस्थानों में मध्य एशियाई सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है और क्षेत्रीय देशों ने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। क्षेत्र से सशस्त्र बलों के लिए सैन्य प्रशिक्षण मुख्य रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया जाता है और कजाकिस्तान , किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के अधिकारी राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी), भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में नियमित रूप से पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं। [45] ताजिकिस्तान क्षेत्र के साथ भारत के सुरक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण देश है।
ताजिकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दुशांबे से करीब 100 किलोमीटर दूर और अफगानिस्तान की सीमाओं के करीब , भारत-ताजिकिस्तान फील्ड अस्पताल (आईटीएफएच) का दौरा किया , जो

भारत द्वारा बनाया गया है और 2014 के अंत से कार्य कर रहा है।[46] आईटीएफएच को भारत के विदेश मंत्रालय वित्त-पोषित किया गया है और वर्तमान में भारत से लगभग 70 लोगों का एक दल अस्पताल में काम कर रहा है जो मरीजों को चिकित्सा , शल्य-चिकित्सा, एनेस्थिसियोलॉजी, प्रसूति-रोग और दंत्य-शल्यचिकित्सा आदि के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।[47]

भारत और मध्य एशिया सुरक्षा सहयोग में एससीओ के लिए नई दिल्ली की पूर्ण सदस्यता के साथ और भी वृद्धि हो सकती है। एससीओ की आतंकवाद-रोधी शाखा विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से आतंकवाद-विरोधी सैन्य अभ्यास करती है। भारत एससीओ की आतंकवाद-रोधी सरंचना[48] से लाभान्वित हो सकता है और इस चुनौती से लड़ने में अपना स्वयं का अनुभव भी साझा कर सकता है। आतंकवाद से निपटने के अलावा, एससीओ, जिसने अफगानिस्तान पर एक संपर्क समूह भी बनाया है , अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है , जो भारत या दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग प्रदान करता है। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में एससीओ की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखता है।[49]

भारत - मध्य एशिया संयोजनता

यद्यपि भारत और मध्य एशियाई देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंध , घनिष्ठ पारस्परिकता के बावजूद, अपनी क्षमता से काफी नीचे रहे हैं। तजाकिस्तान का गोर्नो-बदख्शान क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन भारत के पास मध्य एशिया के लिए कोई सीधी भू-मार्गीय पहुंच नहीं है तथा व्यापार और वाणिज्य आदान-प्रद्दन के लिए हिंद महासागर के माध्यम से एक लंबा चक्कर लगना पड़ता है। मध्य एशियाई

गणराज्य स्थलरुद्ध हैं तथा प्रत्यक्ष संयोजनता का अभाव और किसी तीसरे देश पर निर्भरता द्विपक्षीय व्यापार में बाधा बन रही है। भारत ने क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर 2000 में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे

(आईएनएसटीसी)[2] का शुभारम्भ किया था , जो ईरान और मध्य एशिया के माध्यम से दक्षिण एशिया को पूर्वी यूरोप से जोड़ने की परिकल्पना करता है।

अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबी जरांज-डेलाराम सड़क अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संयोजनता बढ़ाने के लिए भारत की ओर से किया गया एक अन्य प्रयास है। इसका निर्माण भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से किया गया था।[50] दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान की सड़क ईरानी सड़क नेटवर्क को चाबहार और ईरानी गारलैंड सड़क नेटवर्क के साथ जोडती है , जो आगे मध्य एशियाई देशों के सड़क नेटवर्क से जुड़ी हुई है। इसे 2009 में पूरा किया गया और अफगान प्राधिकारियों को सौंप दिया गया।

परमाणु समझौते के बाद, आईएनएसटीसी के एक पक्षकार ईरान पर प्रतिबंध हटाने को हाल के हफ्तों में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित भारत, ईरान, रूस (तीन संस्थापक सदस्यों)[51] और दस अन्य देशों की हाल ही में आयोजित एक बैठक में पारगमन और सीमा-शुल्क समझौतों के मसौदे को मंजूरी दी, जिससे जहाज-रेल-सड़क मार्ग पर माल ढुलाई के लिए विधिक ढांचा प्रदान किया गया।[52]। बैठक के दौरान, भारत के विदेश सचिव , एस जयशंकर ने भी कॉरिडोर को चालू करने के लिए एक अंतर-देशीय एजेंसी बनाने का प्रस्ताव दिया। [53] फरवरी 2016 में, रूसी और अज़रबैजान रेलवे ने आईएनएसटीसी नेटवर्क की भारत-ईरान-अजरबैजान-रूस लाइन के माध्यम से भारत और रूस के बीच कार्गो परिवहन के लिए टैरिफ को अंतिम रूप दिया।[54]

---

[2] *आईएनएसटीसीआई कन्वेंशन में हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देश हैं: भारत , ईरान, रूस,*

बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, ओमान, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन।

इस लिंक के माध्यम से पहली ट्रेनें जल्द ही शुरू होने की आशा है। वर्तमान में, भारत के मुंबई बंदरगाह से मास्को तक और समुद्री मार्ग के माध्यम से रूस के यूरोपीय क्षेत्रों तक लगभग 40 दिन लगते हैं ; हालाँकि, नया आईएनएसटीसी लिंक शुरू में परिवहन समय को घटाकर लगभग 20 दिन और बाद में इसे 14 दिन कर देगा।[55]

अपने अलगाव को तोड़ने के लिए , मध्य एशियाई देशों ने भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ने और अपने परिवहन और वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ाने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय पहलकदम उठाए हैं। क्षेत्रीय देशों ने 2011 में अश्गाबत व्यापार और पारगमन समझौते का शुभारंभ किया।[56] तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने ईरान और ओमान के साथ अश्गाबात समझौते का शुभारंभ किया , जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच पूर्व-पश्चिम गलियारा बनाता है। कजाकिस्तान फरवरी 2015 में समझौते में शामिल हुआ। [57] मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए , प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र की यात्रा के दौरान, आईएनएसटीसी और अश्गाबात समझौते के विस्तार का आह्वान किया और आईएनएसटीसी में तुर्कमेनिस्तान को और अश्गाबात समझौते में भारत को शामिल करने मांग की। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति श्री गुरबंगुली बर्दीमुहम्मदोव ने अश्गाबद समझौते में शामिल होने के भारत के आशय का स्वागत किया।[58]

फिर भी , हाल ही में 925 किलोमीटर लम्बी ईरान-तुर्कमेनिस्तान-कजाकिस्तान रेल लाइन के उद्घाटन के साथ ही, ईरान के माध्यम से मध्य एशिया के लिए संयोजनता आसान हो गई है। [59] रेल के माध्यम से पश्चिम एशिया को मध्य एशिया से जोड़ने के अलावा , यह रेल लाइन, जो दिसंबर 2014 से परिचालन में है, उत्तर-दक्षिण अक्ष के साथ, अब कैस्पियन सागर

को हिंद महासागर से भी जोड़ती है। इस संपर्क ने आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की है और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिसके 2020 तक 15 मिलियन टन तक पहुंचने की आशा है।[60] दिसंबर 2014 में तुर्कमेनिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान , कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नजरबायेव ने रेलवे को "मध्य पूर्व का एक द्वार" कहा और यह उल्लेख किया: 'फ़ारस की खाड़ी की ओर रेलवे संपर्क बन जाने से , वर्तमान वर्ष में कज़ाकिस्तान के व्यापार में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। "[61] इस संपर्क का उपयोग करते हुए , भारतीय बंदरगाहों से माल मध्य एशिया और ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों के माध्यम से आगे अफगानिस्तान तक भेजा जा सकता है। । भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश कर रहा है और यह ईरान , मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक इसकी पहुंच को बढ़ाएगा। बंदरगाह का उपयोग कच्चे तेल और यूरिया का परिवहन करने के लिए किया जाएगा और भारत के लिए परिवहन की लागत और समय को बचाएगा , तथा देश 10 साल के लिए चाबहार में दो बर्थ पट्टे पर लेना चाहता है।[62]

जुलाई 2015 में वियना में ईरान-5+1 परमाणु समझौते के सफल निष्पादन ने मध्य एशिया की दुनिया के साथ बेहतर संपर्क होने की आशा को और बढ़ा दिया है। इन गणराज्यों ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को इस देश के माध्यम से परिवहन क्षमता का उपयोग करने में बाधा के रूप में देखा क्योंकि यह खुले समुद्रों के लिए व्यवहार्य , अल्प और अधिक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। मध्य एशियाई गणराज्यों ने कूटनीति के माध्यम से परमाणु डोजियर के शुरुआती प्रस्ताव का समर्थन किया और कजाकिस्तान ने ईरान और छह शक्तियों के बीच 2013 में दो-दौर की परमाणु वार्ता की मेजबानी करने की पहल की।[63] ईरानी मार्ग की उपलब्धता भारत और मध्य एशिया के बीच माल और खनिजों के परिवहन की तेज गति और कम लागत के साथ अनुमति देती है। आर्थिक क्षमता के अलावा , ईरान मध्य

एशियाई देशों को अपने हाइड्रोकार्बन ऊर्जा संसाधनों को बेचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करता है। मध्य एशिया की यात्रा के दौरान , प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अशांत क्षेत्रों से बचते हुए तुर्कमेनिस्तान गैस को एक भू-समुद्री मार्ग के माध्यम से ईरान के रास्ते भारत पहुंचने वाले एक और मार्ग की संभावना तलाशने का सुझाव दिया।[64]

अपने क्षेत्र में पहुँच प्रदान करने से इंकार करते हुए भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुँच से दूर रखने में विफलता को भांपते हुए , पाकिस्तान ने अब मध्य एशिया के साथ दक्षिण एशिया की संयोजनता को आसान बनाने के लिए संकेत देना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान-पाकिस्तान पारगमन व्यापार समझौता (एपीटीटीए) 2010 पाकिस्तानी क्षेत्र के माध्यम से अफगान माल के आवागमन की अनुमति देता है। यह करार अफगान ट्रकों को वाघा सीमा तक अफगान ट्रांजिट निर्यात कार्गो लाने की अनुमति भी देता है , जहां कार्गो को भारतीय ट्रकों में लादा जाता है। हालांकि, पाकिस्तान वाघा सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए भारतीय निर्यात की अनुमति नहीं देता है और कहता है कि इस बारे में "भविष्य में उचित समय पर चर्चा की जा सकती है।"[65]

हाल ही में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी तजाकिस्तान को शामिल करने के लिए अपने ट्रांजिट व्यापार समझौते के दायरे को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की है।[66] इस तरह के समझौते में भारत को शामिल करने से मध्य एशियाई देशों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2015 में भारत के दौरे पर आई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति घानी के साथ नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में कहा कि भारत 'अफगानिस्तान के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता चाहता है जिसमें भारत को एपीटीटीए शामिल करता हो'।[67] ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन असलोव ने भारत की अपनी हाल

की यात्रा के दौरान पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान व्यापार और ट्रांजिट समझौते में चौथे भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए नई दिल्ली की रुचि का स्वागत किया। [68] इस बीच, पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि वह भारत को द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक पार्टी बनाने और स्थलरुद्ध अफगानिस्तान के साथ पारगमन समझौते पर विचार करेगा।[69]

दो क्षेत्रों के बीच व्यापार और संयोजनता को सुविधाजनक बनाने और उसमे वृद्धि करने की क्षमता रखने वाली एक और बहुपक्षीय प्रक्रिया 'इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ' (टीआईआर) कन्वेंशन है। [70] यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा-शुल्क ट्रांजिट प्रणाली है और 'एकमात्र ऐसी सार्वभौमिक ट्रांजिट प्रणाली है जो मूल देश से गंतव्य के देश को आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से सीमा-शुल्क नियंत्रण मान्यता के साथ मॉल के सीलबंद लोड डिब्बों में पारगमन को अनुमति देता है। । यह प्रशासनिक और वित्तीय बोझ को कम करता है तथा सीमा-शुल्क और कर, जो देय हो सकते हैं , एक अंतर्राष्ट्रीय गारंटी द्वारा कवर किए जाते हैं। [71] अफगानिस्तान सम्मेलन का एक संविदाकार पक्ष है और मध्य एशियाई देशों में टीआईआर लागू है। हाल ही में , पाकिस्तान कन्वेंशन का साठवां संविदा पक्षकार बन गया है , जो देश के लिए जनवरी 2016 से लागू हो रहा है। [72] भारत भी कन्वेंशन में शामिल होने के लिए इच्छुक है। [73] चूंकि ईरान भी कन्वेंशन का प्रचालनात्मक पक्षकार है, परमाणु सौदे के उपरांत का परिदृश्य आर्थिक जुड़ाव के लिए अधिक संभावनाओं की शुरूआत कर सकता है। इस प्रकार के व्यापार सुविधा समझौते के माध्यम से निकट आर्थिक संबंध और एकीकरण हासिल करने में मदद मिल सकती है।[74]

हालांकि भारतीय व्यवसायों और माल अग्रेषणकर्ताओं को मध्य एशिया के साथ भू-संयोजनता मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, एक ऐसा क्षेत्र, जहां

भारत के पास बढ़त है और उस क्षेत्र के लोगों से जुड़ने में उसे कोई समस्या नहीं होती है , साइबर संयोजनता है। देश ने उन्नत संचार प्रणाली और उपकरण विकसित किए हैं और यह आईटी उद्योग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सोर्सिंग गंतव्य है। [75] यह विभिन्न क्षेत्रों में इस क्षेत्र में टेली-सेवाओं की पेशकश कर सकता है। किर्गिज़ गणराज्य में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान , एक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया था , जो किर्गिस्तान के विभिन्न भागों में चिकित्सा सुविधाओं को भारत के अति-विशिष्ट अस्पतालों से जोड़ती है। यह भारत और मध्य एशिया के बीच पहला टेली-चिकित्सा लिंक है। [76] किर्गिज़ अनुभव को अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ अन्य क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए , शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण में ; भारत और मध्य एशियाई देशों के मानक समय के बीच थोड़ा समय-अंतर है। यह भारत के लिए एक लाभ है, जो अन्य प्रमुख क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। टेली-कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों को कम निवेश के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करता है और इसके लिए बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण और बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। भारत को सभी मध्य एशियाई देशों के लोगों के मध्य अपार सद्भावना प्राप्त है और टेली-कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं , जो सीधे उपलब्ध हैं और आम लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, तथा इसे और भी मजबूती करती हैं।

मध्य एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण

मध्य एशिया के साथ-साथ दक्षिण एशिया में भी क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। रूस , कजाकिस्तान और बेलारूस द्वारा स्थापित ईईयू 1 जनवरी 2015 को प्रवर्तित हुआ। यह संघ दुनिया की लगभग 15 प्रतिशत भूमि को कवर करता है और अब इसमें आर्मेनिया और किर्गिज़ गणराज्य भी सदस्यों के रूप में शामिल हो गए हैं। साझे यूरेशियाई आर्थिक

स्पेस का विचार कजाखस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव द्वारा 1994 में प्रस्तुत किया गया था।. [77] तथापि, यूक्रेनी संकट और प्रतिबंधों के कारण इसने विकर्षण हासिल किया क्योंकि रूस एक बार फिर मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशियाई देशों ने इस पहल को भिन्न दृष्टिकोण से देखा। कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य इसके सदस्य हैं। ताजिकिस्तान अभी भी सदस्य बनने के लिए चुनौतियों और आर्थिक लाभ का मूल्यांकन कर रहा है। तथापि , यथाशीघ्र यह निर्णय लेने की आवश्यकता होगी कि क्या मास्को रूसी शहरों में रहने वाले ताजिक प्रवासियों की बड़ी संख्या और देश में रूसी सैन्य ठिकानों की उपस्थिति को देखते हुए , दुशनाबे को ईईयू में शामिल होने के लिए दृढ़ता से आग्रह करता है। उज़बेकिस्तान इस पहल में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसका संभवतः यह कारण है कि वह आर्थिक रूप से कजाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। [78] तुर्कमेनिस्तान एक तटस्थ देश है और इसके तेल और गैस की आय और रूसी अल्पसंख्यकों की छोटी आबादी रूस को उस देश पर अधिक दबाव डालने की अनुमति नहीं देती है।[79]

भारत ईईयू के साथ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र करार पर बातचीत कर रहा है और उसने एफटीए की व्यवहार्यता पर कजाकिस्तान के साथ एक संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया है। [80] प्रधानमंत्री की इस क्षेत्र में यात्रा के दौरान, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के साथ एफटीए वार्ता को 'शीघ्र पूरा' करने का आग्रह किया [81] और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संयुक्त अध्ययन समूह की स्थापना का स्वागत किया और कहा कि एफटीए भारत और कजाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए एक 'समर्थकारी वातावरण' का निर्माण कर सकता है।[82]

दूसरी ओर, चीन ने यूरोप के लिए निर्यात हेतु अपने परिवहन नेटवर्क के साथ मध्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम के भाग के रूप में अपनी सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट का सुभारंभ किया है। मध्य एशियाई देश और साथ ही रूस पारस्परिक हितों के लिए चीन की परियोजना का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। भारत ने अब तक क्षेत्र में इस चीनी परियोजना का भाग बनने की इच्छा नहीं जताई है ; तथापि, नई दिल्ली ने यूरेशिया में एक अन्य चीनी पहल - एससीओ की पूर्ण सदस्यता के लिए अनुरोध किया है। यह संगठन इस क्षेत्र के समक्ष आ रही आतंकवाद और उग्रवाद की आम सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हो रहा है।

एससीओ में भारत का समावेश और पूर्ण सदस्यता क्षेत्र में देश की भागीदारी और ऊर्जा हितों में वृद्धि कर सकती है। एससीओ का उद्देश्य संयोजनता में सुधार करना, आतंकवाद से लड़ना, ऊर्जा सहयोग में वृद्धि करना और मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए उपाय करना है, जिन उद्देश्यों को भारत द्वारा यूरेशिया में साझा किया गया है।[87] एससीओ बड़े ऊर्जा उत्पादकों जैसे रूस और कजाकिस्तान तथा बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं जैसे भारत और चीन को भी एक मंच पर लाता है। दिसंबर 2013 में, एससीओ सदस्यों ने एससीओ ऊर्जा क्लब के सृजन पर एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऊर्जा क्लब बनाने का विचार पहली बार 2004 में प्रस्तावित किया गया था , हालांकि एससीओ सदस्यों के इस पर अलग-अलग विचार थे। कुछ विशेषज्ञों में टिप्पणी की है कि ऊर्जा क्लब एक 'साझा ऊर्जा स्पेस' का अग्रदूत हो सकता है।[88] एससीओ का साझा ऊर्जा स्पेस परिवहन के लिए ऊर्जा संसाधन टैरिफों को उदार और मानकीकृत बना सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पादक

देशों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को टालने के लिए उनकी ओर से की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय किया जा सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत का एससीओ में शामिल होना इसे अधिक संतुलित क्षेत्रीय संगठन बनाता है क्योंकि मध्य एशियाई गणराज्यों ने भारत की परिकल्पना 'सॉफ्ट संतुलनकर्ता' के रूप में की है।[89]

भारत और मध्य एशिया की समन्वित संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए , प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान में कहा: "भारतीय और इस्लामी सभ्यता का संगम मध्य एशिया में हुआ।" [92] भारत और मध्य एशियाई देश आतंकवाद और उग्रवाद के संकट का सामना कर रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से इस चुनौती से निपटने प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि आम विरासत ने अतिवाद को खारिज कर दिया है: "भारत और मध्य एशिया, दोनों की इस्लामी विरासत को इस्लाम के उच्चतम आदर्शों - ज्ञान, पवित्रता, करुणा और कल्याण द्वारा परिभाषित किया गया है। यह विरासत प्रेम और भक्ति के सिद्धांत पर स्थापित की गई है। और , इसने हमेशा चरमपंथ की ताकतों को खारिज किया है" और...."आज , यह ताकत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो भारत और मध्य एशिया को एक साथ लाता है।"[93]

भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम हैं , जिसके माध्यम से संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। [94]कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र नृत्य प्रदर्शन और योग कार्यक्रम आयोजित करके क्षेत्र में भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के कार्य में लगे हुए हैं और वे मध्य एशियाई लोगों के लिए योग और नृत्य की नियमित कक्षाएं भी संचालित करते हैं।

1997 में, नई दिल्ली ने फेर्गाना घाटी क्षेत्र में किर्गिस्तान के दक्षिणी भाग में ओश विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र खोला। इस केंद्र में भारतीय विद्वान आया करते थे और विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ाते थे, जिनमें से कई अन्य पड़ोसी मध्य एशियाई देशों से भी थे जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ाते थे। तथापि, हिंसा और असुरक्षा की स्थिति के कारण इसे 2010 में बंद कर दिया गया था। चूँकि अब देश की स्थिति स्थिर हो गई है, मध्य एशिया में नई पीढ़ी के बीच भारत के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए इस केंद्र को फिर से खोला जा सकता है।

भारतीय संस्कृति के अन्य क्षेत्र भी मध्य एशियाई देशों में लोकप्रिय हैं , विशेष रूप से , बॉलीवुड सिनेमा। भारतीय फिल्में , विशेष रूप से हिंदी फ़िल्में, क्षेत्र में हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत की अधिकांश हिंदी फिल्में रूसी भाषा में और फिर क्षेत्रीय भाषाओं में डब की जाती हैं, जो पूरे क्षेत्र में मौजूदा स्टोरों पर लोगों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। वस्तुतः , इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता भारतीय फिल्म उद्योग को अपनी भारतीय फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग के लिए किफायती और नज़दीकी स्थान उपलब्ध करती है। इससे भारत में फिल्म उत्पादन लागत में कमी करने और क्षेत्र में भारतीय सिनेमा बाजार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले , मध्य एशियाई देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया। तुर्कमेनिस्तान ने अश्गाबत में योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की है , जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस क्षेत्र की यात्रा के दौरान किया था।[95]

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 'विभिन्न क्षेत्रों में भारत और किर्गिस्तान के

बीच संस्कृतिक सहयोग को गहन बनाने जैसे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, लोक कलाओं, रंगमंच, युवा उत्सवों के आयोजन' के संबंध में भारत और किर्गिस्तान के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए। '[96] भारत-तुर्कमेनिस्तान संयुक्त वक्तव्य में 'दोनों देशों के बीच संस्कृति पर सहयोग के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने' का आह्वान किया गया। [97] भारत और ताजिकिस्तान ने सहयोग के एक कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें 'दोनों देशों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण , परिरक्षण और संवर्धन में विशेषज्ञता के आदान-प्रदान' के माध्यम से संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग' की परिकल्पना की गई है। [98] इसके अलावा, भारत और कजाकिस्तान के बीच 'भौतिक संस्कृति और खेल' के क्षेत्र में एक समझौता-ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।[99] नई दिल्ली ने ताशकंद के साथ 2015-17 के लिए सांस्कृतिक सहयोग के अंतरसरकारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।[100]

विविध सांस्कृतिक संबंधों के साथ , भारत और मध्य एशिया के बीच लोगों के लोगों के साथ संपर्क और सद्भाव को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक और आर्थिक संबधों में अधिक सहयोग मिलेगा।

सहयोग के लिए संभावना

प्रधानमंत्री की इस क्षेत्र की यात्रा ने मध्य एशियाई व्यापारिक समुदाय और आम लोगों के मध्य भारत के बारे में उत्साह को बढ़ाया है , जो देश और इसकी जीवंत संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हैं। मध्य एशिया में आर्थिक विकास में वृद्धि होने से निर्माण , इंजीनियरिंग, परामर्श, प्रबंधन सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास और जावक पर्यटन में गतिविधियां में तेजी आई है। भारत ने इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता को बढ़ाया है। क्षेत्र में भारतीय भेषजिक उत्पादों की काफी मांग है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान , भारत ने क्षेत्र में

देश के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार कजाकिस्तान के साथ एक संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना की। अब , भारतीय निजी क्षेत्र को मध्य एशिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने और क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि पैन-यूरेशियन बाजार को शामिल किया जा सके। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण भारत और मध्य एशिया के बीच सहयोग का एक अन्य आशाजनक क्षेत्र है। क्षेत्र के देशों में कृषि-योग्य भूमि के बड़े हिस्से हैं जिनमें पानी की प्रचुरता और जनसंख्या का कम दबाव है। जैविक खेती और जैविक उत्पादों के लिए भी पर्याप्त गुंजाइश है , जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक निकटवर्ती यूरोपीय बाजारों में मांग है। इसके अलावा , कृषि सहयोग भारत की खाद्य सुरक्षा में भी योगदान कर सकता है।

इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और यह क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के महत्वपूर्ण समय में आयोजित हुई। रूस, चीन और ईरान निवेश के माध्यम से मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं तथा बहुपक्षीय संगठन और क्षेत्रीय देश अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक संतुलन के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपस्थिति चाहते हैं, ताकि कोई भी शक्ति क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण बनाने में सक्षम न होने पाए। भारत के महत्व , स्थिरता, अनुभव और आर्थिक क्षमताओं को महसूस करते हुए , यूरेशियाई देशों ने एससीओ की सदस्यता, ईईयू के साथ प्रस्तावित ईटीए और अश्गाबात ट्रांजिट करार में संभावित सदस्यता के रूप में नई दिल्ली के साथ मजबूत संबंध और अधिक-से-अधिक सहभागिता स्थापित करने का पक्ष लिया है।

यह देखा गया है कि मध्य एशिया के घटनाक्रमों को भारत के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में बहुत स्थान दिया गया है। दोनों पक्षों के लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने

और छोटे और मध्यम उद्यमों को पड़ोसी क्षेत्रों में विद्यमान अवसरों के बारे में सूचित किए जाने की आवश्यकता है। भारत ने उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की है। नई दिल्ली मध्य एशियाई देशों के साथ इस क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेटवर्क के लिए एक समर्पित उपग्रह पर काम कर सकती है। एक-दूसरे के बारे में अधिक जानकारी प्रदान से भारत और मध्य एशिया के बीच पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मध्य एशिया की यात्रा के साथ, भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने इस क्षेत्र के साथ आर्थिक, ऊर्जा, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और लोगों-के-लोगों के साथ संबंधों में वृद्धि करने और उन्हें के लिए उचित आधार तैयार किया है। भारतीय शिक्षण संस्थानों में छात्रों और शोधकर्ताओं को क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण देने के अलावा क्षेत्र पर शोध को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के व्यापारिक अग्रेताओं , चिकित्सकों, शिक्षाविदों, मनोरंजन उद्योग और मीडिया स्रोतों के लिए आवश्यक है कि वे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के पारस्परिक विकास के लिए संबंधों का निर्माण करने और उन्हें व्यापक बनाने के लिए कार्य करें।

पाद-टिप्पणियां

1. सुहासिनी हैदर , "ए काउंटरपॉइंट टू चाइना इनरोड्स" , *द हिंदू*, 21 मई 2015, to-chinas-inroads/article7228668.ece (10 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

2. हेमंत एस. एट अल. , "इंडिया सेंट्रल एशिया बैकग्राउंडर ," सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, 6 जून 2014, http://idcr.cprindia.org/blog/india- central-asia-backgrounder (10 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

3. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के कार्यालय , "अफगानिस्तान पर इस्तांबुल प्रक्रिया के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में राष्ट्रपति घानी द्वारा वक्तव्य ," बीजिंग, चीन, 31 अक्टूबर 2014, http://president.gov. af / en / news / statement-by-President-ghani- at-heart-of-asia-istanbul-process-4th-ministerial-conference (12 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

4. शंघाई सहयोग संगठन , "शंघाई सहयोग संगठन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ अफगानिस्तान के बीच एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की स्थापना पर प्रोटोकॉल" 7 मई 2009 , http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=70 (17 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

5. दिमित्री सोलोयोव , " कमांडर ऑफ एलीट ताजिक पुलिस बल डेफेक्ट्स टू इस्लामिक स्टेट ," रायटर, 28 मई 2015 , http: // www। reuters.com/article/2015/05/28/us-mideast-crisis-tajikistan-idUSKBN0OD1AP20150528 (25 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)
6. राकेश सूद , ' मुल्ला उमर: ए मिथ ऑफ कन्वीनिएंस ', द हिंदू, 20 अगस्त 2015, http://www.thehindu.com/opinion/lead/mullah- omar-a-

myth-of-convenience/article7558254.ece?homepage=true (25 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)

7. वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन , "यूरेनियम एंड न्यूक्लियर पावर इन कजाकिस्तान" जून 2015 , http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Kazakhstan/, (22 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।
8. इंडेक्स मुंडी , "उज्बेकिस्तान इकॉनमी प्रोफाइल 2014 ," http: // www। indexmundi.com/uzbekistan/economy_profile.html, (27 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।
9. जोशुआ कुसेरा , "उज्बेकिस्तान: मिलिट्री ऐड टू ताशकंद वुड हेल्प प्रोटेक्ट एनडीएन - स्टेट डिपार्टमेंट ," 28 सितंबर 2011 , http: // www। eurasianet.org/node/64237 (12 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

10. विदेश मंत्रालय, ताजिकिस्तान गणराज्य, "ताजिकिस्तान गणराज्य का ऊर्जा क्षेत्र," http://mfa.tj/en/energy-sector/-energy-sector-of-rt.html, (5 अगस्त, 2015)।
11. "आउटपुट कट एट कुमटोर गोल्ड माइन स्लो किर्गिज़ जीडीपी ग्रोथ इन 2014," *रॉयटर्स*, 15 जनवरी 2015, http://www.reuters.com/ आर्टिकल / 2015/01/15 / kyrgyzstan-gdp-idUSL6N0UU2K820150115 (17 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।
12. एशियाई विकास बैंक , “TAPI संचालन समिति TAPI गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए कंसोर्टियम लीडर के रूप में तुर्कमेन्गाज़ का समर्थन करती है ,” 7 अगस्त 2015 , http://www.adb.org/news/tapi-steering-committee-endorses- turkmengaz-consortium-leader-tapi-gas-pipeline-project(12 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)

13. "तुर्कमेनिस्तान कंट्री प्रोफाइल ," बीबीसी, 10 सितंबर 2015 , http://www.bbc। com / news / world-asia-16094646 (12 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

14. विश्व बैंक, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP। CD / देशों / KZ-7E-XT? प्रदर्शन = डिफ़ॉल्ट (12 सितंबर 2015 तक पहुँचा)
15. अतुल अनेजा , "ट्रेन टू मैड्रिड अनवेल्स न्यू सिल्क रोड ड्रीम ," 12 दिसंबर 2014 को प्रकाशित , http://www.thehindu.com/news/international/world/train-to-madrid-unveils-new-silk-road-dream/article6686501.ece (10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

16. जिन्हुआ, "रेगुलर ट्रेन्स लिंक चोंगकुइंग, जर्मनीज़ डुइसबर्ग," 8 अप्रैल 2014, http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-04/08/c_133246484.htm (12 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)
17. ओलज़्हास अयुज़ोव, "लैंडलॉक कजाखस्तान चैलेंज़ेस सी शिपर्स फॉर चाइना-ईयू कार्गो ," रायटर, 26 अक्टूबर 2015 , http: // www.reuters.com/article/2015/10/26/kazakhstan-china-trade-idUSL8N12M3YZ20151026 (30 अक्टूबर 2015 को एक्सेस किया गया)
18. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार, "तेज कदम: भारत - कजाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य," 8 जुलाई 2015 , http://mea. gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25437/Tej_Kadam_India__Kazakhstan_Joint_Statement (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

19. "कजाकिस्तान भारत को यूरेनियम की आपूर्ति के लिए सहमत है ," विश्व परमाणु समाचार , 8 जुलाई 2015 , http://www.world-nuclear-news.org/UF- Kazakhstan-agrees-to-supply-uranium-to-India-0807156.html (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।
20. दीपांजन रॉय चौधरी , "मध्य एशिया में पीएम मोदी की यात्रा: यूरेनियम आपूर्ति, रक्षा पर भारत और कजाखस्तान ने सौदे पर हस्ताक्षर किए" , *दि इकोनॉमिक टाइम्स* , 9 जुलाई 2015 , http://economictimes.indiatimes.com/

articleshow/47996585.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst (9 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

21. "ऑयल एंड गैस सेक्टर ," कज़ मुनाई ज़ाज़ , http://www.kmgep.kz/eng/about_kazakhstan / oil_and_gas_sector / (10 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

22. 'ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ," माननीय प्रधान मंत्री ने कजाखस्तान में सत्पयेव में ड्रिलिंग का सुभारंभ किया , "14 जुलाई 2015,http://www. ongcindia.com/wps/ wcm/connect/ ongcindia/ home/media/ press_ release/honble-pm-launches-drilling-at-satpayev (26 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

23. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , 11 जुलाई 2015 , http: // mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25456/Joint_Statement___Turmenistan_and_India_during_the_Prime_Ministers_ visit_to_Turkmanistan (Access) (10 सितम्बर अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

24. ज़फ़र भुट्टा , "पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान टू गिव बिग पुश टू टीएपीआई प्रोजेक्ट", दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून, 6 अगस्त, 2015 , http://tribune.com.pk/story/932965/gas-pipeline-pakistan-turkmenistan-to-give-big-push-to-tapi-project/ (10 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

25 मारत गुर्ट , "अपडेट 1-तुर्कमेनिस्तान टू स्टार्ट वर्क ऑन टीएपीआई पाइपलाइन इन दिसम्बर ," *रायटर्स*, 15 सितम्बर 2015, http: // uk.reuters.com/article/2015/09/15/turkmenistan-pipeline- idUKL5 N11L0RE20150915 17 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

26 एशियाई विकास बैंक, "टीएपीआई स्टीयरिंग कमिटी एन्डोर्सेस तुर्कमेन्गाज़ एज

कंसोर्टियम लीडर फॉर टीएपीआई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ," 7 अगस्त 2015, http://www.adb.org/news/tapi-steering-committee-endorses-turkmengaz-consortium-leader-tapi-gas-pipeline-project (10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

27 पीआईबी, "पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने तुर्कमेन के फैसले का स्वागत किया है, जो दिसंबर 2015 में पाइपलाइन के तुर्कमेन खंड का निर्माण शुरू करने के लिए नया बल प्रदान करता है ," 6 अगस्त 2015 http://pib.nic.in/newsite/pmreleases.aspx?mincode=20 (10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

28. "नवाज़ ने तुर्कमेनिस्तान को तापी के तेजी से क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया ," *दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून* , 20 मई 2015 , http://tribune.com. pk/story/889763/nawaz-pushes-turkmenistan-to-fast-track- implementation-of-tapi/(14 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

29. पेनस्पैन , "पैंसपेन अवारडेड तुर्कमेनिस्तान , अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया (टीएपीआई) पाइपलाइन फीजिएबिलिटी स्टडी ," 13 अक्टूबर 2014 , http:// www.penspen.com/asia-pacific/penspen-awarded-turkmenistan-afghanistan-pakistan-india-tapi-pipeline-feasibility-study/((10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

30. पाइपलाइन इंटरनेशनल , "पेनस्पैन अवारडेड टेक्निकल फीजिएबिलिटी स्टडी फॉर 1 ,820 किमी टीएपीआई पाइपलाइन " 14 अक्टूबर 2014 , http: // pipelinesinternational.com/news/penspen_awarded_technical_ fotibility_study_for_1820_km_tapi_pipeline/089433/5 (5 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

31. श्री एम. हामिद अंसारी , भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा मैरी , तुर्कमेनिस्तान में टीएपीआई गैस पाइपलाइन परियोजना के उद्घाटन

समारोह में संबोधन , 13 दिसंबर 2015 , http://vicepresidentofindia.nic.in/contents.asp?id=557 (10 फरवरी 2016 को एक्सेस किया गया) ।

32. यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम , "अफ़गानिस्तान के साथ सेंट्रल एशिया की सीमाओं को सुरक्षित करना" , सितंबर 2007 , https://www.unodc.org/documents/ regional/central-asia/Microsoft%20Word%20-%20yellow_paper no%20maps_16.09.17.pdf (19 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।
33. सौले मुखमित्रखिमोवा , "सेंट्रल एशिया एट रिस्क फ्रॉम पोस्ट -2017 अफगानिस्तान," आईडब्ल्यूपीआर, 20 अगस्त 2013 , https://iwpr.net/global-voices/ central-asia-risk-from-post-2014-afghanistan, (5 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।
34. आईसीजी, "सीरिया कॉलिंग: रैडीकलाइज़ेशन इन सेंट्रल एशिया ," 20 जनवरी 2015, http://www.crisisgroup.org/en/regions/ asia/central-asia/b072-syria-calling-radicalisation-in-central-asia.aspx (28 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

35. "ताजिकिस्तान के मंत्री नज़रजोदा सरकारी बलों द्वारा मारे गए ," बीबीसी, 16 सितंबर 2015 , http://www.bbc.com/news/world-asia-34275455 (20 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।
36. "ताजिकिस्तान कंफर्म्स डेथ ऑफ़ म्युटिनस फॉर्मर डिप्टी डिफेन्स मिनिस्टर ," *रेडियो फ्री यूरोप* , 16 सितंबर , 2015, http: // www। rferl.org/content/tajikistan-renegade-general-killed/ 27251919 .html (20 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।
37. "ताजिकिस्तान के मंत्री नज़रजोदा सरकारी बलों द्वारा मारे गए ," बीबीसी, 16 सितंबर 2015 , http://www.bbc.com/news/world-asia-34275455 (20 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।
38. "ताजिकिस्तान सेज़ इट हैज़ किल्ड रेनेगेड एक्स-मिनिस्टर" *वीओए न्यूज़*, 16 सितंबर 2015 http://www.centralasianews. net/index.php/ sid /

236794093 (20 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

39. रोमन कोजेव्निकोव और ओल्गा डेज़ीबेंको , "मध्य एशियाई प्रवासियों को रूस के आर्थिक मंदी का दर्द महसूस होता है ," *रायटर्स*, 2 दिसंबर 2014 , http://www.reuters.com/article/2014/12/02/us-europe-demographics-centralasia-idUSKCN0JG13S20141202 (11 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।
40. डेनियल टुरोव्स्की, "हाउ आइसिस इज़ रिक्रूटिंग माइग्रेंट वर्कर्स इन मॉस्को टू ज्वाइन दि फाईटिंग इन सीरिया ," 5 मई 2015 , http://www.theguardian.com/world/2015/may/05/isis-russia-syria-islamic-extremism (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया) ।
41. जैकोपो डेटोनी , तात्याना ड्रोनज़िना के साथ साक्षात्कार , "साक्षात्कार: मध्य एशिया में आईएसआईएस ," 11 अगस्त 2015 , http://thediplomat.com/2015/08/ interview-isis-in-central-asia/ (10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया) ।
42. " उज्बेकिस्तान बैंस चिल्ड्रेन फ्रॉम मोस्क्स ऑन ईद अल-अधा फेस्टिवल , *रेडियो फ्री लिबर्टी* , 27 सितंबर 2015 , http://www.rferl.org/content/uzbekistan-bans-children-from-mosques-for-eid/27268142. html (27 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।
43. "तालिबान कनडेम्स 'इर्रेस्पोंसिबल, इग्नोरेंट' आईएसआईएस फॉर ग्राफिक एक्सेक्यूशन ऑफ़ अफगान प्रिसिनर्स," *आरटी*, 12 अगस्त 2015, https: // www। rt.com/news/312256-taliban-isis-condemns-killing/ (14 अप्रैल 2015 को एक्सेस किया गया)।
44. "पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की: आतंक , अफगानिस्तान पर चर्चा हुई ," 6 जुलाई 2015 , http://articles.economictimes. indiatimes.com/2015-07-06/news/64142860_1_pm-modi-prime- minister-narendra-modi-india-and-uzbekistan (13 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

45 विनोद अनाद (सं.) , "भारत-मध्य एशिया रक्षा और सुरक्षा सहयोग: चिंतन और संभावनाएं" , *ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पर परिप्रेक्ष्य - मध्य एशिया संबंध:*

संभावनाएँ और मुद्दे में , पीपी. 22-25-25 , विज बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2011

46 "पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत-ताजिक फील्ड अस्पताल का दौरा किया" , जी न्यूज़, 13 जुलाई 2015 , http://zeenews.india.com/news/india/pm-narendra-modi- विज़िट-india-tajik-field -161629570. html, (17 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

47 रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार , "वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 ," पी. 98 , http://mod.nic.in/writereaddata/AR1415.pdf (6 अक्टूबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

48 पी. स्टोबडान , "एससीओ में भारत का हिस्सा और दुविधा" , 8 जून 2015 , आईडीएसए, http://www.idsa.in/idsacomments/ IndiasStakesandDilemmainSCO_ pstobnan_080615.html (10 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

49 संदीप दीक्षित, 'भारत को लगता है कि एससीओ अफगानिस्तान में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है ', *द हिंदू* , 1 दिसंबर 2013 , http: //www.thehindu। com / news / india-feel-sco-can-play-a-big-role-in-afghanistan / article5411255.ece (6 अक्टूबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

50 विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , "भारत और अफ़गानिस्तान: विकसित भागीदारी" http://mea.gov.in/Uploads/ PublicationDocs / 176_india-and-afagonistan-a-development- partnership .pdf (7 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

51. शंकर शिंदे/श्री सोहेल एफ काजनी, "इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी)," *फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया* , http://instcindia.in//uploads/ गैलरी / 143460437414_india_pretation.pdf (6 अक्टूबर 2015 को एक्सेस किया गया)

52. दीपांजन रॉय चौधरी , "आईएनएसटीसी ड्राफ्ट अनुमोदन: भारत-ईरान-रूस कॉरिडोर पर आगे बड़ा कदम ," *द इकोनॉमिक टाइम्स* , 2 सितंबर 2015 ,

http://articles.economictimes.indiatimes.com /2015-09-02/news/66144139_1_india-iran-russia-corridor-project-north-south- transport-corridor (8 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)

53. तदेव

54. न्यूज़.एजेड "मार्च के अंत तक अजरबैजान के माध्यम से रूस से भारत के लिए पहली ट्रेन भेजी जाएगी," 16 फ़रवरी 2016 http://news.az/articles/economy/105179 (22 फरवरी 2016 को एक्सेस किया गया)।

55. तदेव

56. "अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना पर करार अश्गाबात में हस्ताक्षरित," *तुर्कमेनिस्तान.आरयू,* 26 अप्रैल 2011 http: // www.turkmenistan.ru/en/articles/14816.html, (10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

57. "कजाखस्तान उजबेकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान-ओमान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल," *दि टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया* , 17 फरवरी 2015 , http:// www.timesca.com/news/14989-kazakhstan-joins-uzbekistan-turkmenistan-iran-oman-transport-corridor, (17 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

58. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , "प्रधानमंत्री की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के दौरान तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच संयुक्त वक्तव्य ," 11 जुलाई 2015, http://www.mea.gov.in/ bilateral-documents.htm?dtl/25456/Joint_Statement_between_ Turkmenistan_and_India_during_the_Prime_Ministers_visit_to_ Turkmenistan, (14 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

59. उमिद नयेश , "कजाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान रेलवे का उद्घाटन" , 3 दिसंबर 2014 , http://en.trend.az/iran/ business/2339779.html (17 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

60 वुसला अब्बासोवा , "कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान मुल ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन ," *एज़र न्यूज़* , 10 जून 2015 , http://www.azernews.az/

region/83390.html, (4 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

61. "2015 में कजाखस्तान ईरान को अनाज निर्यात पांच गुना बढ़ा सकता है: राष्ट्रपति नज़रबायेव ," *टेंगरी न्यूज़* , 23 मई 2015 , http:// en.tengrinews.kz/markets/Kazakhstan-may-increase-grain-exports- to-Iran-five-times-in-260445/ (27 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।
62. इंडिया, ईरान साइन एमओयू ऑन डेवल्पिंग चाबहार पोर्ट, 6 मई 2015,http://www.livemint.com/Politics/pZhLxBv6GqyDLRK 5tK2mHI/ India-Iran-sign-pact-on-developing-Chabahar-port.html. (10 मई 2015 को एक्सेस किया गया)।
63. गालियास्कर सेत्थान इन यूरेशिया एंड वर्ल्ड, "ईरान न्यूक्लियर डील पॉजिटिव न्यूज फॉर कजाकिस्तान, वर्ल्ड, एमएफए सेज़," अस्ताना टाइम्स, 17 जुलाई 2015, http://www.astanatimes.com/2015/07/iran-nuclear-deal-positive-news-for-kazakhstan- world-mfa-says/. (15 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।
64. "पीएम नरेंद्र मोदी का टीएपीआई गैस पाइपलाइन परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए बल ," *दि इकोनॉमिक टाइम्स* , 11 जुलाई 2015 , http://articles. economictimes.indiatimes.com/2015-07-11/news/64308814_1_ gas-pipeline-project-prime-minister-narendra-modi-india-and- turkmenistan (14 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

65 "अगला पड़ाव: ताजिकिस्तान ," *पाकिस्तान टुडे*, 20 जुलाई, 2012, http: // www। pakistantoday.com.pk/ 2012/07/20 / news / profit / next-stop-tajikistan / (13 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

66. अफगानिस्तान पर दिल्ली निवेश शिखर-सम्मेलन , "भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक संबंध ," http://www.dsafagan.in/pdf/India-Afaganis tan.pdf (23 जुलाई 2013 को एक्सेस किया गया)।

67. सुहासिनी हैदर, "पाकिस्तान को व्यापार के लिए वाघा खोलना चाहिए: घानी," *द हिंदू*, 30 अप्रैल 2015 , http://www.thehindu.com/news/national/pakistan-must-open-wagah-for-trade-ghani / article7155457.ece (20 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

68 "ताजिकिस्तान ट्रेड पैक्ट में भागीदार के रूप में भारत की रूचि का स्वागत करता है ," *दि इकोनॉमिक टाइम्स* , 12 मई 2015 , http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-05-12/news/62082528_1_trade-agreement- trade-pact-world-affairs (एक्सेस 10 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

69. अयाज गुल , "पाकिस्तान नॉट अपोज़ टू इंडिया जोइनिंग अफगान ट्रांजिट ट्रीटी" 16 अप्रैल 2015 , http://www.voanews.com/content/pakistan-not-opposed-india-joining-afghan-transit-treaty/2722428.html (10 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)

70. पीर मुहम्मद, "सुचारू व्यापार: टीआईआर कन्वेंशन ने कानूनी ढांचे के लिए स्वीकृति प्राप्त की , *द एक्सप्रेस ट्रिब्यून* , 27 मई 2015 , http://tribune.com.pk/story/892814/smooth-trade-tir-convention-gets-approval-for-legal-framework/. (10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

71. "टीआईआर सिस्टम के बारे में ," अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन संघ , https://www.iru.org/en_iru_about_tir (10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)

72. "पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र टीआईआर कन्वेंशन में शामिल हुआ ," 24 जुलाई 2015, http://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/transport/2015/pakistan-joins-the-united-nations-tir-convention/pakistan-joins-the-united-nations-tir-convention.html (10 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

73. टीआईआर जियोग्राफिक स्कोप , इच्छुक पार्टियां, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन, https://www.iru.org/en_iru_tir_scope_inde (10 सितंबर

2015 को एक्सेस किया गया)।

74. टीआईआर जियोग्राफिक स्कोप , इच्छुक पार्टियां , इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन, https://www.iru.org/en_iru_tir_scope_inde (10 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।
75. "आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री इन इंडिया ," इंडिया ब्रैड इक्विटी फाउंडेशन , सितंबर 2015, http://www.ibef.org/industry/information- technology-india.aspx (27 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।
76. "पीएम मोदी ने भारत और मध्य एशिया के बीच पहले टेलीमेडिसिन लिंक का उद्घाटन किया ," *एएनआई न्यूज ,* 13 जुलाई 2015 , http://www.aninews.in/ newsdetail2/story224321/pm-modi-inaugurates-first-elemedicine- link-between-india-and-central-asia.html (27 सितंबर 2015 को एक्सेस किया गया)।
77. "यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 1 जनवरी से लागू , एकीकरण से लाभ का वादा," अस्ताना टाइम्स , 2 जनवरी 2015 , http:// astanatimes.com/2015/01/eurasian-economic-union-comes-force-jan-1-promising-benefits-integration/. (19 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।
78. दिनारा उराज़ोवा , "कजाखस्तान, उजबेकिस्तान और यूरेशियन संघ ," *टेंगरी न्यूज़,* 11 फरवरी 2015 , http://en.tengrinews.kz/politics_sub/ Kazakhstan-Uzbekistan-and-Eurasian-Union-258935/ (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया) ।
79. बेयराम बाल्सी , एकातेरिना कासिमोवा , "हाउ सेंट्रल सेंट्रल रिपब्लिक्स द इमर्सिंग द इमर्जिंग यूरेशियन यूनियन ," कार्नेगी, 24 जनवरी 2015 , http://carnegieendowment.org/2015/ 01/24/how-central-asian-republics-perceive-emerging-eurasian-union (25 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।
80. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार, "तेज कदम: भारत - कजाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य", 8 जुलाई 2015 , http://mea. gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25437/Tej_Kadam_India__

Kazakhstan_Joint_Statement (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

81 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "किर्गिज़ गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच संयुक्त वक्तव्य , " 12 जुलाई 2015 , http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25462/ Joint_Statement_between_the_Kyrgyz_Republic_and_the_ Republic_of_ndia (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

82 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "तेज कदम: भारत - कजाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य," 8 जुलाई 2015 , http://mea. gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25437/Tej_Kadam_India__ Kazakhstan_Joint_Statement (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

83 "पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स, एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल रूस का दौरा करेंगे ," *दि इंडियन एक्सप्रेस* , 7 जुलाई 2015 , http://indianexpress. com/article/india/india-others/pm-narendra-modi-to-visit-russia- tomorrow-to-attend-brics-sco-summits/#sthash.KrNJqhy4.dpuf (14 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

84 "भारत, पाकिस्तान पूर्ण एससीओ सदस्य बने *", दि हिंदू*, 11 जुलाई 2015, http://www.thehindu.com/news/international/india-gets-full-membership-of-the-shanghai-cooperation-organisation-along-with-pakistan/article7407873.ece (14 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

85 "कजाखस्तान एससीओ के लिए भारत और पाकिस्तान के परिग्रहण का समर्थन करता है ," *टेंगरी न्यूज* , 11 जुलाई 2015 , http://en.tengrinews.kz/politics_sub/ Kazakhstan-supports-accession-of-India-and-Pakistan-to-SCO- 261190/ (20 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

86. जोशुआ कुचेरा , "भारत के बारे में चिंतित केंद्रीय एशियाई , पाकिस्तान

एससीओ में शामिल हुआ ," 15 जुलाई 2015 , http://www.eurasianet.org/node/74226 (20 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

87 "एससीओ में भारत के प्रवेश का स्वागत ," *डेक्कन हेराल्ड*, 13 जुलाई 2015, http://www.deccanherald.com/ content/488900/ indias-entry-sco-welcome.html, (14 अगस्त 2015 को एक्सेस किया गया)।

88. "एससीओ मेम्बर्स इंक मेमो ऑफ़ क्रिएशन ऑफ़ एनर्जी क्लब," *एशिया प्लस*, 8 दिसंबर 2013 , http://news.tj/en/news/sco-members-ink-memo-creation-energy-club (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया))।

89. निर्मला जोशी , "भारत और शंघाई सहयोग संगठन: एक विश्लेषण ," विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन , 3 अप्रैल 2015 , http://www.vifindia.org/article/2015/April/03/india-and-the-shanghai-cooperation-organization-an-analysis#sthash.EyPDxtsQ.dpuf (14 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

90. लोकेश चंद्र , "अफगानिस्तान और भारत: हिस्टोरिको-कल्चरल पर्सपेक्टिव". अफगानिस्तान में संकट: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य , के. वारिकू द्वारा संपादित , नई दिल्ली: भवन बुक्स, 2002, पीपी। 1-15।

91. रॉय-चौधरी, राहुल. टोबी डॉज और निकोलस रेडमैन (सं.) में. अफगानिस्तान टू 2015 एंड बियॉन्ड (द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज , लंदन: रूटलेज, 2012) पृ. 231.

92. "नज़रबायेव विश्वविद्यालय, अस्ताना, कजाकिस्तान में पीएम द्वारा संबोधन का पाठ ," प्रेस सूचना ब्यूरो , भारत सरकार , 7 जुलाई 2015 , http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid-123050 (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

93. तदेव

94. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित "भारत-मध्य एशिया संबंधों का संवर्धन और अन्य मुद्दे" पर एक सेमिनार में सचिव (पूर्व) द्वारा संबोधन , 18 मार्च 2013 , http://www.mea.gov.in/ Speeches-Statements.htm?dtl/21540/Address+by+Secretary+East+ at+a+Seminar +on+ Enhancing+IndiaCentral+Asia+Engagement+Pr ospects+and+Issues +organized+by+The+United+Service+Institutio n+of+India (7 अक्टूबर 2015 को एक्सेस किया गया)।

95. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , "तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच प्रधान मंत्री की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य ," 11 जुलाई 2015, http://www.mea.gov.in/ bilateral-documents.htm?dtl/25456/Joint_Statement_between_ Turkmenistan_ and_India_during_the_Prime_Ministers_visit_to_ Turkmenistan. (14 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

96. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , "प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करारों की सूची- किर्गिज़ गणराज्य ," 12 जुलाई 215 , http: //www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm? Dtl / 25461 / List_of_agreements_signed_during_Prime_Ministers_visit_to_the_ Kyrgyz _Republic। (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

97. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , "तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच प्रधान मंत्री की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य ," 11 जुलाई 2015,

http://www.mea.gov.in/ bilateral-documents.htm?dtl/25456/Joint_Statement_between_ Turkmenistan_and_India_during_the_Prime_Ministers_visit_to_ Turkmenistan. (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

98. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, "प्रधानमंत्री की ताजिकिस्तान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करारों की सूची , 13 जुलाई 2015 , http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25464/ List_of_ Agreements_signed_during_Prime_Ministers_visit_to_ Tajikistan_ July_1213_2015. (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

99. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , "तेज कदम: भारत - कजाखस्तान संयुक्त वक्तव्य", 8 जुलाई 2015 , http://www.mea. gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25437/Tej_Kadam_India__ Kazakhstan_Joint_Statement (20 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।

100. विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , "प्रधान मंत्री की उजबेकिस्तान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करारों की सूची ", 7 जुलाई 2015 , http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25433/List+of+ Agreements+signed+during+the+Visit+of+Prime+Minister+ to+Uzbekistan+67+July+2015 (15 जुलाई 2015 को एक्सेस किया गया)।